

\$~

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि 04.12.2023

वसियती वाद सं. 17/2023, अंतर.आ 4359/2023 (अंतरिम राहत)

अंतर.आ 4360/2023 (पुनर्स्थापना)

विकास मल्होत्रा

..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री संजीव महाजन सह श्री ऋषभ
वाष्ण्य, श्री एस.एस.चंद्रा,
अधिवक्तागण के साथ याचिकाकर्ता
स्वयं रूप से,

बनाम

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री कनक बोस, प्रत्यर्धी-2 के
अधिवक्ता।

श्री करण नागरथ, सुश्री नूपुर कुमार,
श्री अंबुज तिवारी, सुश्री मुस्कान
नागपाल, श्री अर्जुन नागरथ,
अधिवक्ता प्रत्यर्धी-3 के लिए
अधिवक्ता।

श्री वाई.पी.नरूला, वरिष्ठ अधिवक्ता
सह श्री अभय नरूला, प्रत्यर्थागण 4
और 5 के लिए अधिवक्ता।

श्री उजास कुमार, प्रत्यर्धी-7 के लिए
अधिवक्ता।

सुश्री दामिनी चावला, प्रत्यर्थागण 8
और 9 के लिए अधिवक्ता.

कोरम:

माननीय एम. न्यायाधीश रेखा पल्ली

न्या.. रेखा पल्ली (मौखिक)

अंतर.आ 23155/2023

1. यह प्रत्यर्था संख्या 4 और 5 द्वारा दायर एक आवेदन है। 4 और 5 ने जिसमें प्रोबेट याचिका के जवाब के माध्यम से आपतियां दर्ज करने में 85 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है। चूंकि आपतियां इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 06.07.2023 के आदेश के माध्यम से दिए गए छह सप्ताह के समय की समाप्ति के 85 दिनों के बाद दायर की गई हैं, इसलिए 85 दिनों की उपरोक्त अवधि की माफी की मांग करने वाला वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।

2. आवेदन के समर्थन में, आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. पी. नरूला प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर उत्तर दाखिल नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्यर्था संख्या 5, जो प्रत्यर्था संख्या 4 की माँ है। वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उचित निर्देश देने की स्थिति में नहीं थी। इसके अलावा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार कई वर्षों से पिछले मुकदमे में शामिल रहे हैं, एक प्रभावी जवाब दाखिल करने के लिए पिछली कार्यवाही का पूरा विवरण आवश्यक था, जिसे प्रत्यर्था संख्या 5

याचिका पर आपतियों का मसौदा तैयार करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 या उनके अधिवक्ता को देने में सक्षम नहीं था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 8 और 9 के लिए भी आवेदन का जोरदार विरोध किया गया है। जबकि याचिकाकर्ता न केवल देरी की माफी की मांग करने के कारणों की अपर्याप्तता के आधार पर आवेदन का विरोध करता है, बल्कि इस आधार पर भी कि इस न्यायालय के पास 120 दिनों से अधिक समय तक जवाब दायर करने की स्थिति में देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है, प्रत्यर्थी संख्या 2,3,8 और 9 केवल अपर्याप्त कारणों के आधार पर आवेदन का विरोध करते हैं।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महाजन प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 06.07.2023 पर, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण को जवाब दाखिल करने के लिए संशोधित याचिका की सेवा की तारीख से छह सप्ताह का समय दिया था। प्रत्यर्थीगण को दिनांक 13.07.2023 पर संशोधित याचिका की एक प्रति दी गई है, उन्होंने केवल 19.11.2023 पर अपना जवाब दाखिल करने का विकल्प चुना है, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष नियम), 2018 (इसके बाद, 'नियम') के अध्याय 7 में निर्धारित 120 दिनों की अवधि के बाद दिनांक 10.11.2023 को पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

5. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की अधिनियम 295 (इसके बाद 'अधिनियम') की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए, वह प्रस्तुत करते हैं कि

जिन मामलों में 'वसीयत' का विरोध किया जाता है, वहां वसीयती याचिका की कार्यवाही, जो अन्यथा नियमों के अध्याय 29 द्वारा शासित होती है, को एक नियमित वाद के रूप में किया जाना आवश्यक है, जिस पर नियमों का अध्याय 7 स्पष्ट मुकदमा से लागू होता है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि प्रत्यर्थागण ने 14.03.2022 पर, जब वर्तमान याचिका को प्रारंभिक विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया था, एक अभिवाक दायर की थी कि वसीयत मान्य नहीं थी, इसलिए यह पहले दिन से ही स्पष्ट था कि यह एक विवादित मामला था जिसमें प्रत्यर्थागण को अधिकतम 120 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की आवश्यकता थी। इसलिए, उनका तर्क है कि इस न्यायालय के पास प्रत्यर्था संख्या 4 और 5 द्वारा आपतियां दायर करने में 120 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है।

6. वह आगे प्रस्तुत करता है कि विलंब की माफी की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा उल्लिखित आधार भी बेहद अस्पष्ट हैं और अभिलेख से उत्पन्न नहीं हुए हैं। आवेदकों ने अपनी याचिका के समर्थन में कोई चिकित्सा दस्तावेज संलग्न नहीं किए हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 के बीमार स्वास्थ्य के कारण आपतियां दायर नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा, देरी की माफी की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन पर भी अकेले प्रत्यर्था संख्या 4 द्वारा हस्ताक्षर किए हैं, जो, आवेदक के मामले के अनुसार, किसी भी चिकित्सा समस्या से पीड़ित नहीं था। प्रत्यर्था संख्या 5, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह

अस्वस्थ था, उसने न तो आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही सहायक शपथ पत्र पर और इसलिए आवेदक प्रत्यर्थी संख्या की कथित बीमारी का कोई लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

7. प्रत्यर्थी सं. 2, 3, 8 & 9 के विद्वान् अधिकवता भी श्री श्री महाजन द्वारा की गई दलीलों को यह तर्क देने के लिए भी स्वीकार करते हैं कि विलंब की क्षमा की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा दिए गए आधार अपर्याप्त हैं। इसलिए वे आवेदन को खारिज करने की भी मांग करते हैं।

8. जवाब में, आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, **मालिनी मेहरा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य एम.ए.एन.यू./डी.ई./1128/2022** मामले में एक समन्वय पीठ के निर्णय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि यह न्यायालय पहले ही मान चुका है कि नियमों के अध्याय 7 के प्रावधान वसीयती मामलों पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 295 में प्रावधान है कि एक विवादित वसीयतनामा मामले में कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार एक नियमित वाद के मुकदमा में आयोजित की जानी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियमों के अध्याय 7 की सख्त कठोरता, जैसा कि एक सिविल वाद पर लागू होती है, स्वचालित रूप से वसीयतनामा याचिकाओं पर लागू होगी।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, मैंने पाया कि वर्तमान आवेदन में मेरे विचार के लिए दो मुद्दे उत्पन्न होते हैं। पहला याचिकाकर्ता अभिवाक के संबंध में है कि इस न्यायालय के पास संशोधित याचिका की सेवा की तारीख से 120 दिनों के बाद याचिका पर आपत्तियां/जवाब दाखिल करने में देरी को माफ करने की शक्ति नहीं है। दूसरा यह है कि क्या वर्तमान मामले में आवेदकों द्वारा उठाए गए आधार याचिका पर आपत्तियां दायर करने में 85 दिनों की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त हैं।

10. नियमों के अध्याय 7 और अध्याय 29 दोनों के प्रावधानों को देखने के बाद, मैं श्री वाई पी नरूला की अभिवाक् प्रतिगृहीत करने के लिए इच्छुक हूं कि केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 295 में प्रावधान है कि एक विवादित वसीयतनामा याचिका में कार्यवाही एक नियमित मुकदमे में संचालित की जानी चाहिए, इसका मतलब यह नहीं होगा कि नियमों का अध्याय 7 स्वचालित मुकदमा से वसीयतनामा याचिकाओं पर लागू होगा। वास्तव में, जो सामने आता है वह यह है कि इस वसीयती अधिकार क्षेत्र की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जहां न्यायालय से किसी ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं को लागू करने की आवश्यकता होती है, जो अब अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उपलब्ध नहीं है, नियमों के अध्याय 29 में ऐसी किसी भी सख्त समय-सीमा का प्रावधान नहीं है जो अध्याय 7 द्वारा शासित दीवानी मुकदमे पर लागू होती है।

अन्यथा भी, मुझे यह भी पता चलता है कि अधिनियम की धारा 295 के प्रावधानों में केवल यह कहा गया है कि एक विवादित वसीयती याचिका में कार्यवाही, जितना संभव हो सके, एक दीवानी मुकदमे के मुकदमा में आयोजित की जाएगी। श्री महाजन इस मुकदमे में यह आग्रह करने में गलत हैं कि एक वसीयतनामा याचिका की सुनवाई बिल्कुल एक सिविल वाद की तरह की जानी चाहिए या एक सिविल वाद पर लागू होने वाली कठोर समय सीमा को एक वसीयतनामा याचिका पर भी लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, मेरा विचार है कि एक वसीयती याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय का प्रयास तकनीकी आधारों पर आपत्तियों को अस्वीकार करने का नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि वे अत्यधिक देरी के साथ दायर की गई हैं।

11. इस संबंध में *मालिनी मेहरा (पूर्वोक्त)* में निर्णय के पैरा 11 से 18 का संदर्भ दिया जा सकता है, जिस पर आवेदकों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है, जिसमें न्यायालय ने अधिनियम की धारा 295 के प्रावधानों के साथ-साथ नियमों के अध्याय 7 और 29 पर भी विचार करने के बाद, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“11. अध्याय 7 के नियमों का उसके शीर्षक के साथ अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उक्त अध्याय केवल इस न्यायालय के समक्ष दायर सिविल वाद के संबंध में लागू होता है। नियम 5, जैसा कि उपरोक्त में कहा गया है, प्रदान करता है कि प्रतिकृति, जिसे 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना है, केवल 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि में दायर की जा सकती है और

उसके बाद नहीं। 45 दिनों (30+15 दिन) की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद, वादी प्रतिकृति दाखिल करने का अपना अधिकार खो देता है, जैसा कि राम सरूप लुगानी (पूर्वोक्त) में खण्ड पीठ द्वारा देखा गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष), नियम, 2018 के अध्याय 29 का शीर्षक "वसीयतनामा और वसीयतनामा क्षेत्राधिकार" है और विशेष रूप से वसीयतनामा मामलों से संबंधित है। अध्याय 29के नियम 1 और 2 में उस तरीके का प्रावधान है जिसमें प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान के लिए याचिकाएं दायर की जानी हैं। उक्त अध्याय याचिका पर आपतियां दायर करने या आपतियों/प्रत्युत्तर का जवाब दाखिल करने के लिए किसी भी समय सीमा का प्रावधान नहीं करता है। आपतियाँ दायर करने के संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई समय सीमा भी नहीं दी गई है। इसलिए, य आपतियां/प्रत्युत्तर का जवाब दाखिल करने के सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित करना न्यायालय का विवेकाधिकार है निस्संदेह, इस विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायालय द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

13. चूँकि अध्याय 7 स्वयं वसीयतनामा मामलों पर लागू नहीं होता है, स्पष्ट रूप से, उपरोक्त अध्याय के नियम 5 को वसीयतनामा मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, नियम 5 केवल एक मुकदमा में "प्रतिकृति" का संदर्भ देता है न कि एक वसीयतनामा मामले में दायर की जाने वाली "आपतियों का जवाब जवाब" नहीं देता है। अध्याय 7 के नियम 5 में 45 दिनों के भीतर दाखिल नहीं किए जाने पर प्रतिकृति दाखिल करने के अधिकार को बंद करने के कठोर परिणाम का प्रावधान है। मेरे विचार में, निहितार्थ से, यह नियम वसीयतनामा मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता है, जब ऐसा नियम विशेष रूप से वसीयतनामा मामलों पर लागू नहीं किया गया है।

14. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 पर भरोसा किया है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“295. विवादास्पद मामलों में प्रक्रिया।—किसी भी मामले में जिला न्यायाधीश के समक्ष, जिसमें विवाद है, कार्यवाहियां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों के अनुसार, एक नियमित मुकदमे का रूप लेंगी, जिसमें यथास्थिति, प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के लिए याचिकाकर्ता वादी होगा, और जो व्यक्ति अनुदान का विरोध करने के लिए उपस्थित हुआ है, वह प्रतिवादी होगा।”

15. धारा 295 में प्रावधान है कि विवादास्पद वसीयतनामा मामलों में कार्यवाही एक नियमित वाद के मुकदमा में और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार होगी। हालांकि, कार्यवाही विवादास्पद है या नहीं, यह मामले में दलीलें पूरी होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए, धारा 295 अभिवचनों की प्रतिस्पर्धा के बाद ही लागू होगी और इस पर यह तर्क देने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष), नियम, 2018 में प्रदान की गई प्रतिकृति दाखिल करने की समय सीमा, वसीयतनामा कार्यवाही पर भी लागू होगी।

16. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उपरोक्त नियमों के अध्याय 1 के नियम 14 और 16 की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, जो नीचे दिए गए हैं:

“14. नियमों के अनुपालन से अभिमोचन करने की न्यायालय की शक्ति।—

न्यायालय, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, पक्षकारों को इन नियमों की किसी भी आवश्यकता के अनुपालन से पक्षकारों को माफ कर सकता है, और व्यवहार और प्रक्रिया के मामलों में ऐसे निर्देश दे सकता है, जिन्हें वह न्यायसंगत और समीचीन समझता है।

[बशर्ते कि जहां न्यायालय/न्यायाधीश की राय है कि व्यवहार दिशानिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है, वह इसे माननीय मुख्य न्यायाधीश के लिए उपयुक्त संदर्भ बना सकता है।]

...

16. न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति प्रभावित नहीं हुई।-

इन नियमों में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्यायाधीश के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।”

17. उपरोक्त अध्याय और ऊपर निर्धारित नियम इस न्यायालय के मूल पक्ष क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों पर लागू होंगे, जिसमें सिविल वाद के अलावा वसीयतनामा के मामले भी शामिल होंगे।

18. नियम 16 न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्तियां देता है जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या न्याया की विफलता को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में, आपतियों का प्रत्युत्तर/जवाब किसी भी स्तर पर दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय का

याचिकाकर्ता द्वारा आपतियों का जवाब दाखिल करने में देरी के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट होना होगा।

12. इसलिए, मुझे याचिकाकर्ता की अभिवाक में कोई गुणा गुण नहीं मिलती है कि 120 दिनों से अधिक की आपतियों को दायर करने में देरी को माफ करने की मांग करने वाला ऐसा आवेदन विचारणीय नहीं है या यह कि न्यायालय किसी भी आत्यन्तिक रूपिस्थिति में याचिका की तामील की तारीख से 120 दिनों से अधिक समय तक दयार की गई आपतियों को दायर करने में देरी को माफ नहीं कर सकता है ।

13. अब आवेदकों द्वारा निर्धारित आधारों की पर्याप्तता के संबंध में दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदक का प्राथमिक अभिवाक यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 5, जो दो आपतिकर्ताओं में से एक है, उसकी आयु लगभग 81 वर्ष है और वह अपने खराब स्वास्थ्य के कारण प्रत्यर्थी संख्या 4 दूसरे आपतिकर्ता, जो उसका पुत्र है या अधिवक्ता है। को उचित निर्देश नहीं दे सका आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार आग्रह किया है कि पक्षों के बीच पिछली अंतर-कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा सार्थक आपतियाँ दायर नहीं की जा सकती थीं,। जब तक प्रत्यर्थी संख्या 5, से व्यापक निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण आवश्यक निर्देश देने में असमर्थ थी।

14. भले ही याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2, 3, 8 & 9 के विद्वान् अधिवक्ता भी आग्रह करने में सही है की प्रत्यर्थी संख्या 4, जिसे किसी भी चिकित्सा समस्या से पीड़ित नहीं कहा गया था, वे समय पर आपतियां दायर कर सकते थे, मेरा विचार है कि इस विशेष क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जहां याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई वसीयत के प्रोबेट के अनुदान से वसीयतकर्ता के उत्तराधिकार की पूरी पंक्ति में भारी बदलाव होने की संभावना है, इसलिए एक कठोर या अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। एक बार जब यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि पक्षों के बीच पिछले मुकदमे को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 5 के लिए पूरी सामग्री को एकत्रित करना और उसके बेटे प्रत्यर्थी संख्या 4 को उचित निर्देश देना था, जो वह अपने खराब स्वास्थ्य और अधिक उम्र के कारण नहीं कर सकी, आवेदकों की इस याचिका पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा, मैं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि हालांकि आपतियां देर से दायर की गई हैं, याचिकाकर्ता के अनुसार ऐसी कोई गंभीर बड़ी देरी नहीं हुई है, वे 120 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद 9 दिनों के भीतर दायर की गई हैं।

15. उपरोक्त कारणों से, आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार, अनुमति दी जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 4 और 5 द्वारा आपतियाँ दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया गया है। नतीजतन, इन प्रत्यर्थीगण

द्वारा दायर आपत्तियों को अभिलेख पर रिकॉर्ड में लिया जाता है। पीड़ित पक्षकों द्वारा इसका जवाब, यदि कोई हो, छह सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। इसके बाद चार सप्ताह के भीतर, यदि कोई प्रत्युत्तर हो, तो दाखिल किया जाए।

वसियती वाद सं. 17/2023

16. याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेजों के प्रवेश/अस्वीकार और दस्तावेजों की संयुक्त अनुसूची दाखिल करने के लिए दिनांक 14.02.2024 पर विद्वान संयुक्त निबंधक पंजीयक (न्यायिक) के समक्ष सूची बनाएँ ।

17. दिनांक 27.03.2024 पर न्यायालय के समक्ष सूची ।

(न्या., रेखा पल्ली)

दिसंबर 4, 2023

एएल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।